

29/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उप. उनके हारा  
हा.पत्र 07R11 C.P.C. पर बन्द हेतु समय पाह गया।  
दतः वकील पत्रकार को बन्द हेतु  
-थायक्ति में एक अन्वीष्ट यवतर दिया जाता है।  
पत्रावली दि. 13/05/24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

13/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उप. उनके हारा  
हा.पत्र 07R11 C.P.C. पर बन्द की गई एवं वकील वकील  
हारा लिखित बन्द तस्सुत की निम्नकी एक प्रतीवकील  
आश्री को रिजवाइ गई।

पत्रावली परसे हा.पत्र 07R11 C.P.C. पर  
आदेश हेतु दि. 13/05/24 को पेश है।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

14/05/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पत्रकार उप. आश्री व.  
लगभग 8 वीं दौर से तस्सुत हा.पत्र 07R11 C.P.C.  
का रीकार किया जाकर निर्णय तस्सुत से पत्रावली  
में शा.मि. किया गया तस्सुत का तस्सुत हा.पत्र  
अ-तस्सुत द्वारा 212 का 07R11 के तस्सुत तस्सुत  
किया जाता है।

पत्रावली केवल शुमार होकर पत्रावली  
नाम्बर से उप है।

उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)  
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 159/2022

1. मंदिर मूर्ति युगल किशोर जी महाराज जरिये आराधक श्री भागीरथ वैष्णव पुत्र स्व० श्री सीताराम वैष्णव, जाति वैष्णव निवासी खवाखस गैरू जी की गली, पुराना शहर किशनगढ़ जिला अजमेर राज० वगै०

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार किशनगढ़ वगै०

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 11  
सी०पी०सी०

दिनांक: 14/05/2024

उपस्थित: श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थीगण अभिभाषक  
श्री विक्रम सिंह पुरोहित अप्रार्थी सं० 7 अभिभाषक

आदेश

1. यह प्रार्थना पत्र दिनांक 24.03.2023 को अप्रार्थीगण सं० 6 लगायत 8 द्वारा अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 11 सी०पी०सी० के तहत न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि—
  - 2.1 अप्रार्थी संख्या 6 लगायत 8 की ओर निवेदन किया गया है कि प्रार्थीगण ने निम्न अधिकारिता का वाद प्रस्तुत किया जो चलने योग्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अधीन आराजी बाबत पूर्व विभिन्न राजस्व न्यायालय द्वारा प्रतिवादी सं० 9 लगायत 13 के मध्य प्रकरण/विवाद न केवल राजस्व अपील अधिकारी महोदय अपितु राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित हो चुके है। प्रार्थना पत्र अधीन आराजी के सम्बन्ध में विधिक खातेदार के प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 90ए की कार्यवाही की जा चुकी है। प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी की कृषि आराजी के भूमि के कुछ भाग की क्षेत्रफल कुल रकबा 1.9998 यानि की 23919 वर्गमीटर भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तित किये जाने के आदेश किये जा चुके है तथा नगर परिषद किशनगढ़ के यहा समर्पण किये जाने, राजस्व अधिकारी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट प्रारूप 6 के



उपखण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

गलत रूप से पुजारी का नाम दर्ज किया गया है जिसकी घोषणा का अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अधीन इस न्यायालय को ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन रहता है। यह अर्जी उपरोक्त प्रतिवादी ने केवल मात्र इस प्रकरण की कार्यवाही को विलंबित कर, बाधित कर वाद के रहते हुये मंदिर की जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिये प्रस्तुत किया है। वाद में नाबालिग मंदिर की तरफ से इस आशय की घोषणा चाही गयी है कि, वादी शाश्वत नाबालिग मंदिर मूर्ति की उपरोक्त वाद में वर्णित भूमि जिसके बाबत् राजस्व अपील अधिकारी के आदेश दिनांक 07.10.2010 के पश्चात् नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 को अविधिक रूप से दर्ज किया गया है को पुनः वापिस मंदिर के नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा निर्णय दिनांक 14.05.2018 में निम्न आदेश किया था :-

“We are of the opinion that the petitioners/appellants have not joined temple as a party in the first appeal. The order which was passed under order 41 Rule 27 CPC is just and proper. However, it will be binding to the parties in proceedings namely the parties before the first appellate authority, Board of Revenue and before this Court and it will not be binding to the party who were not party in proceedings before the first appellate authority, second appellate authority, learned single Judge and this Court.

Counsel for the appellants contended that temple was not a party. In this regard, we made it clear that the order will be binding to the parties in proceedings.

The appeal stands disposed of.”

ऐसी स्थिति में जब दिनांक 14.05.2018 का आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के अधीन हो गया था तो प्रतिवादी भूमिधारी को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अक्षरशः पालना की जानी चाहिये थी एवं यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण संख्या 435 दिनांक 18.10.2010 को वादी मंदिर का नाम हटाकर प्रतिवादी का नाम दर्ज किया गया, जबकि राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 के अनुक्रम में वादी मंदिर पर राजस्व अपील अधिकारी का निर्णय प्रभावी ही नहीं था। यह तथ्य कई निर्णय से तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की वृहत्त पीठ द्वारा निर्णय किया जा चुका है कि, मंदिर की जमीन के बाबत् पुजारी को किसी भी रूप में खातेदारी नहीं प्रदत्त की जा सकती है। आदेश 7 नियम 11



  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

सी0पी0सी0 के अवधारण में वाद संस्थान की स्थिति एवं वाद अभिवचन को ही दृष्टिगत किया जाना आवश्यक, सारवान रहता है। जबकि वाद के अभिवचन के अनुसार यह वाद माननीय न्यायालय की सुनवाई क्षेत्राधिकारिता में ही न्यस्त करता है। हस्तगत वाद का वादी न तो राजस्व अपील अधिकारी, न ही राजस्व मण्डल, न ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, न ही माननीय उच्चतम न्यायलय में पक्षकार था। स्वयं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 14.05.2018 में इस बाबत् स्पष्टतः अंकन किया है कि

“ We are of the opinion that the petitioners/ appellants have not joined temple as a party in the first appeal. The order which was passed under order 41 rule 27 CPC is just and proper . however, it will be binding to the parties before the first appellate authority, board of revenue and before this court and it will not be binding to the party who were not party in proceedings before the first appellate authority, second appellate authority learned single judge and this Court.

Counsel for the appellants contended that temple was not a party. In this regard, we made it clear that the order will be binding to the parties in proceedings.

The appeal stands disposed of.”

तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी दिनांक 02.11.2018 को राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 14.05.2018 की ही पुष्टि की है। जिसके रहते हुए जिस निर्णय को प्रतिवादी आधारित कर रहा है उसी निर्णय दिनांक 14.05.2018 को आधारित कर वादी ने नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितों के अधीन यह दावा नाबालिग की सम्पत्ति के बाबत् गलत रूप से बिना किसी विधिक आदेश के खातेदारी अधिकारी परिवर्तन के अनुक्रम में रिकार्ड शुद्धिकरण सहित अधिकार घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है। वैसे धारा 144 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की भी इस बाबत् विशिष्ट रूप से प्रावधान करती है। उपरोक्त भूमि आज भी मौके पर कृषि ही है, मौके पर कोई आवासीय जन्य कॉलोनी जैसा कोई विकास नहीं हुआ है, दावा पेश करते समय उपरोक्त भूमि कृषि श्रेणी थी तथा धारा 91-ए का जो आदेश जारी किया गया है वह कूटरचित, कपटपूर्ण आम सूचना अखबार पर वादी की आपत्ति के रहते हुए मंदिर भूमि के बाबत् जारी किया गया है। धारा 90-ए के अधीन मंदिर की भूमि के अधिकारों का समर्पण होना अनुज्ञात ही नहीं है। जहां तक धारा 91-ए का उल्लेख किया है, धारा 91-ए तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के बाबत् ही रहता है एवं नाबालिग मंदिर मूर्ति के संरक्षक लोक



  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

अधिकारी होने से यदि धारा 91-ए के अधीन कार्यवाही है तो वह उचित है। जब पुजारियों के नाम नामान्तकरण संख्या 415 दिनांक 18.10.2010 की त्रुटियुक्त है तो उसके पश्चात् उनके द्वारा किया गया सारा संव्यवहार भी पूर्णतः गलत है। वैसे भी नाबालिग की सम्पत्ति का बैचान जन्म से ही शून्य रहता है तथा माननीय न्यायालय इस पहलू को भी दृष्टिगत करेगी कि, नामान्तकरण दर्ज दिनांक 18.10.2010 को हुआ उसके दूसरे दिन दिनांक 19.10.2010 को किस प्रकार प्रतिवादी सं० 6 लगायत 8 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित करवाया गया है। यह पहलू कानूनन सुस्थापित है कि a document which is abinitio void it is not necessary to get the cancellation of document. प्रतिवादी ने न्यायालय को भ्रमित किये जाने की गरज में "राजस्थान वेक्सीनेशन लिटीगेशन "प्रीविनशन" एक्ट 1915" का उल्लेख किया है ऐसा कोई अधिनियम वर्ष 1915 का वादी के संज्ञान में नहीं है। जहां तक वादी को जानकारी है वर्ष 1915 में राजस्थान राज्य का गठन ही नहीं हुआ था। वैसे भी कोई वाद तार्किक है अथवा वेग यह पहलू साक्ष्य से ही अवधारित किया जा सकता है। इस प्रकार स्वयं प्रतिवादी भी प्रत्यक्ष व परोक्षतः यह स्वीकार करता है कि, साक्ष्य लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् ही इस पहलू को अवधारित किया जावे एवं साक्ष्य का बिन्दू आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० की सीमाओं में नहीं आता है। जब माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय दिनांक 14.05.2018 के आदेश में यह अवधारित कर अंतिम निर्णय तर्कों का विवेचन कर, कर चुकी है कि, वादी नाबालिग मंदिर मूर्ति न तो राजस्व अपील अधिकारी, न ही राजस्व मण्डल में पक्षकार नहीं था इसी कारण से मंदिर के हित प्रभावित नहीं होने के कारण दिनांक 14.05.2018 के आदेश में उल्लेखित किया गया था। यहां पर यह उल्लेख किया जाना पूर्णतः सुसंगत रहेगा कि, प्रस्तुत प्रकरण के प्रतिवादीगण में से किसी ने भी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.05.2018 को यह कथन नहीं किये थे कि, मंदिर पक्षकार नहीं होते हुए भी दिनांक 07.10.2010 के आदेश के जरिये मंदिर का नाम विलोपित किया गया है। यह कानूनन रूप से स्पष्ट है कि, जब कोई पक्ष किसी प्रकरण में पक्षकार नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उस पक्ष पर आदेश प्रभावी नहीं होता है। यह पहलू भी साक्ष्य से ही विचारण किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण सं० 6 लगायत 8 का प्रार्थना पत्र व्यय विशेष हर्जे खर्चे सहित निरस्त एवं प्रकरण का शीघ्रतः गुणानुगुण निस्तारण करने का निवेदन किया।

4. हमारे द्वारा प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील पक्षकारान् की बहस सुनी गई।
- 4.1 वकील अप्रार्थी सं० 6 लगायत 8 ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद अधीन आराजी बाबत् पूर्व विभिन्न राजस्व न्यायालय




उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

द्वारा प्रतिवादी सं० 9 लगायत 13 के मध्य प्रकरण/विवाद न केवल राजस्व अपील अधिकारी महोदय अपितु राजस्व मण्डल अजमेर, माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा निस्तारित हो चुके है। वाद अधीन आराजी के सम्बन्ध में विधिक खातेदार के प्रार्थीगण के पक्ष में धारा 90ए की कार्यवाही की जा चुकी है। अतः धारा 91ए होने के कारण तथा भू परिवर्तन होने की वजह से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकारी नहीं है। वर्तमान में उक्त वाद अधीन कृषि आराजी प्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि आराजी है तथा न्यायालय के आदेश/डिक्री के अनुसरण में प्रार्थीगण सं० 6, 7 व 8 के पक्ष में विधिक बैचान किया गया। अतः वर्तमान में वाद अधीन कृषि आराजी को जिस प्रकार वादीगण बता रहे है राजस्व रिकार्ड में अस्तित्व नहीं है। विधिक खातेदारों के विरुद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। वाद अधीन कृषि आराजी के सन्दर्भ में प्रतिवादी सं० 5 लगायत 8 के पक्ष में न्यायालयों के आदेश/डिक्री के अनुसरण में दी गई खातेदारी अधिकार को जब न केवल राजस्व मण्डल अजमेर, राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा राजस्व अपील अधिकारी अजमेर की डिक्री एवं आदेश दिनांक 07.10.2010 को कभी भी खारिज नहीं किया न ही अपास्त किया। इसका आशय यह है कि उक्त आदेश आज भी अस्तित्व में है तथा उक्त आदेश के अनुसरण में अमल में लाई गई समस्त विधिक कार्यवाहियों में अब किसी प्रकार का परिवर्तन करने का माननीय न्यायालय को कोई अधिकार नहीं है। अतः इस अनुरण में भी माननीय न्यायालय को उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं रहा है। वकील अप्रार्थी सं० 6 लगायत 8 द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2023(3) Civil Court cases 001 (s.c.) Ramisetty Venkatanna & Anr. Vs. Nasyam Jamal Saheb & Ors., 2021(2) CJ(Civ.)(Raj.) page 465 Sua Devi Vs. Shrawanram & Ors. 2019 Supp. (2) S&R (Civ) 1360 Shaukathussain Mohammed Patel Vs. Khatunben Mohmmmedbhai Polara. और 2012(2) RRT Page No. 1096 Ravindra Kumar Vs. Swapan Choudhary & Ors. आदि पेश कर उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 11 सी०पी०सी० के अनुसरण में प्रार्थीगण का वाद/प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया।

4.2 वकील प्रार्थीगण ने अपनी लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि वादीगण/प्रार्थीगण ने यह वाद नाबालिग मंदिर मूर्ति के हितो के संरक्षक बाबत् मंदिर मूर्ति का आराधक होकर प्रस्तुत किया है तथा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के खंड पीठ के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के आदेश के रहते हुये भी मंदिर



  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

के हितों के प्रतिकूल राजस्व प्रविष्टि की गई है एवं तहसीलदार किशनगढ़ के समक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के रिट में पक्षकार थे। फिर भी उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं कर नाबालिग मंदिर मूर्ति की सम्पत्ति को अंतरण खुर्द-बुर्द किये जाने जैसे कृत्यों को एक प्रकार से अनुज्ञा, अनुमति दी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अप्राथी/प्रतिवादी ने न्यायालय के समक्ष गलत कथन किये है। वह न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के समक्ष विक्रय विलेख निरस्तीकरण के वाद में यह कथन करता है कि उपरोक्त श्रेणी के वाद को राजस्व क्षेत्राधिकारिता को सुनने का अधिकार है एवं माननीय न्यायालय के समक्ष वह यह कथन करते है कि यह वाद सिविल क्षेत्राधिकारिता के न्यायालय को सुनने का अधिकार है इस प्रकार एक ही बिन्दू पर समान पक्षकार द्वारा अलग-अलग न्यायालय के अलग-अलग कथन किया जाना केवल मात्र विधिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस पहलू पर प्रतिवादी की नाबालिग की सम्पत्ति को येन-केन प्रकारेण हड़प करने की मनस्थिति को परिलक्षित करता है। आदेश 7 नियम 11 अवधारण समय साक्ष्य के बिन्दू को दृष्टिगत नहीं किया जाना चाहिए तथा आदेश 7 नियम 11 के अवधारण समय केवल मात्र वाद अभिवचन ही निर्धारण के बिन्दू रहते है, जैसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की वृहत पीठ द्वारा अपने न्याय निर्णय में अवधारित किया है। धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का बिन्दू आदेश 7 नियम 11 के अधीन नहीं आता है इस पहलू पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीपति श्री D.Y. Chandrachud द्वारा srihari hanumandas totala Vs Hemant Vithal kamat & Ors में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पहलू आदेश 7 नियम 11(डी) व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन वाद के निरस्तीकरण का आधार नहीं बन सकता है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा दिनांक 14.05.2018 के पारित आदेश में स्पष्टतः यह निर्णय किया है कि उपरोक्त भूमि के बाबत जो राजस्व अपील अधिकारी द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनांक 07.10.2010 है। उसमें वादी मंदिर पक्षकार नहीं होने से वाद मंदिर के हित प्रभावी नहीं होते है जबकि तहसीलदार किशनगढ़ ने उक्त उपरान्त भी दिनांक 07.10.2010 के राजस्व अपील अधिकारी के आदेश के आधार पर नामान्तकरण सं0. 415 दिनांक 18.10.2010 के जरिये मंदिर के स्थान पर पुजारियों का नाम दर्ज किया गया एवं सबसे महत्वपूर्ण पहलू तो यह भी है कि उपरोक्त दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित आदेश के प्रकरण में तहसीलदार किशनगढ़ Officer in Charge थे। इस प्रकार माननीय न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट साक्ष्य है किस प्रकार



  
 उपरवण्ड अधिकारी  
 किशनगढ़ (अजमेर)

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश के उपरान्त भी नाबालिग मंदिर मूर्ति की सम्पत्ति जिसे संरक्षक तहसीलदार किशनगढ़ के साथ-साथ अजमेर जिले में राज्य सरकार के प्रतिनिधित्वकर्ता जिला कलक्टर भी है। माननीय न्यायालय के समक्ष स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध है किस प्रकार नाबालिग मंदिर मूर्ति की बहुमूल्य सम्पत्ति के बाबत भूधारी (Land holder) द्वारा प्रतिवादीगण को लाभ पहुंचाने के लिए कार्यवाही की गई है। वादी इस प्रकरण में माननीय न्यायालय के समक्ष यह कथन करता है कि माननीय न्यायालय इस वाद की सुनवाई के बाबत आदेश 47 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अधीन माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय को दिशा निर्देश से मार्गदर्शन बाबत निम्न बिन्दु पर राय ली जावे। ताकि माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति स्पष्ट हो जावे क्योंकि प्रकरण के किसी भी पक्षकार को यह अधिकार नहीं होता है कि वह न्यायालय को दूल बनाकर कार्यवाही करे :-

(अ) दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ में पारित निर्णय में मंदिर के हित राजस्व अपील अधिकारी के दिनांक 07.10.2010 के आदेश प्रभावी नहीं होने का आदेश किया है एवं उसके उपरान्त भी क्या वादी मंदिर की ओर से दिनांक 07.10.2010 के आदेश के आधार पर मंदिर का नाम हटाकर नामान्तकरण सं० 415 दिनांक 18.10.2010 की कार्यवाही उचित है क्या?

(ब) दिनांक 14.05.2018 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में जिसमें राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार भी पक्षकार था एवं उन्हे इस आदेश का संज्ञान रहते हुए भी राजस्व रिकार्ड में नामान्तकरण सं० 415 दिनांक 18.10.2010 की त्रुटियुक्त प्रविष्टि को विलोपित नहीं किया है। ऐसी स्थिति में क्या नाबालिग मंदिर मूर्ति की ओर से संस्थित वाद उक्त त्रुटियुक्त राजस्व प्रविष्टि के बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन अधिकार घोषणा के अनुतोष अन्तर्गत धारा 88 के बाबत संघारण योग्य रहता है क्या?

(स) क्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 14.05.2018 को पारित आदेश के जरिये राजस्व अपील अधिकारी के निर्णय दिनांक 07.10.2010 का प्रभाव नाबालिग मंदिर मूर्ति वादी के हितो पर भी बाध्यकारी माना है क्या?

यह प्रार्थना पत्र प्रतिवादी ने केवल मात्र प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र जिसे राजस्व अपील अधिकारी ने समय सीमा में निस्तारित किये जाने बाबत निर्देश दिये है एवं प्रतिवादी उपरोक्त भूमि मंदिर के हितो के विपरित नगर परिषद के अधिकारियों से मिलीभगत कर खुर्द बुर्द करना चाहता है एवं इसके रहते हुए यह प्रार्थना पत्र दुर्भावयुक्त आशय से प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय के समक्ष



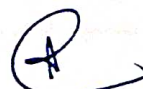
*(Handwritten signature)*

उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

उपरोक्त प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र पैरा सं० 6 में "राजस्थान वेक्सीनेशन लिटीगेशन 'प्रीविनशन' एक्ट 1915" का उल्लेख किया है जबकि उपरोक्त प्रतिवादी द्वारा वर्णित कोई अधिनियम 1915 का नहीं है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में जो उल्लेख किया है वह साक्ष्य से मौहताज है एवं साक्ष्य से मौहताज बिन्दू आदेश 7 नियम 11 के अधीन नहीं आते हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के दिनांक 14.05.2018 के आदेश जिसमें उपरोक्त ख०नं० 186 रकबा 91-18-00 भूमि जो नाबालिग मंदिर मूर्ति के नाम नामान्तरण सं० 415 दिनांक 18.10.2010 के पूर्व दर्ज थी एवं नाबालिग मंदिर मूर्ति राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पक्षकार नहीं था। यह पहलू माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा दिनांक 08.08.2014 एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय दिनांक 14.05.2018 के रहते हुए भी इस तथ्य का संज्ञान रहते हुए नाबालिग मंदिर मूर्ति को खुर्द-बुर्द किये जाने का कोई भी आदेश जन्म से ही शून्यता रखता है। उपरोक्त प्रतिवादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष संभागीय आयुक्त के समक्ष धारा 90(अ) के आदेश के विरुद्ध की गई अपील जो आज भी लम्बित है का लोप किया है। प्रतिवादी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष जानबूझकर मंदिर की भूमि का रकबा 1.9998 हैक्टेयर माननीय न्यायालय को भ्रमित किये जाने के लिए अंकित किया है। आज भी उपरोक्त मंदिर की ख०नं० 186 रकबा 91-18-00 में से काफी भाग कृषि का है। अतः इस परिपेक्ष्य में भी वाद माननीय न्यायालय में ही अवधारणीय रहता है। वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत 2016(1) RRT 485 S.C. The City Municipal Council Bhalki Vs. Gurappa, 2018 SAR (Civil) 739 Supreme Court Canara Bank Vs. N.G. Subbaraya Setty & Anr. और 2007(4) WLC Raj Page 354 Dr. S.P. Mishra Vs. The N.C.E.R.T. & Anr. आदि पेश कर अप्रार्थीगण सं० 6 लगायत 8 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 का खारिज करने का निवेदन किया।

5. हमारे द्वारा अप्रार्थी सं० 6 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 11 सी०पी०सी० एवं शपथ व वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का गहनता से अवलोकन किया गया एवं वकील पक्षकारान् कि ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० सपठित धारा 11 सी०पी०सी० पर बहस सुनकर उस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने से पूर्व ही वादग्रस्त आराजी कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरित हो चुकी थी इस सम्बन्ध में राजस्थान



  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ (अजमेर)

काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 में राजस्व न्यायालय द्वारा संदेय वाद और आवेदन के बाबत् प्रावधान दिये गये है :-

“207. Suits and applications cognizable by revenue court only – (1) All suits and application of the nature specified in the Third Schedule Shall be heard and determined by a revenue court. (2) No court other than a revenue court shall take cognizance of any such suit or application or of any suit or application based on a cause of action in respect of which any relief could be obtained by means of any such suitor application.

Elplanation- if the cause of action is one in respect of which relief might be granted by the revenue court, it is immaterial that the relief asked for from the civil court is greater than, or additional to, or is not identical with, that which the revenue court could have granted.”

और उक्त कथन के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत 2012(2) आर.आर.टी. पृष्ठ संख्या 1096 का अवलोकन किया गया जिसमें स्पष्ट विवेचन किया है :-

“The jurisdiction of Civil Court is saved as soon as the pure character of land in question as agriculture land, is lost and that becomes an abadi land though by virtue of some statute or de facto by user thereof for residential purposes or purposes other than agriculture.”

जिसमें राजस्व अदालत को मात्र कृषि आराजी से सम्बन्धित वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित है जैसे ही आराजी की प्रकृति कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरित होगी उसका क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय में निहित हो जायेगा।

यह मान भी लिया जाए की प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी की खातेदारी उद्घोषणा के लिए पेश किया गया है जो यह विधिक स्थिति भी स्पष्ट है की वाद पत्र में वर्णित आराजी बाबत् माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय अजमेर के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07.10.2010 को बहाल रखते हुए प्रतिवादी सं० 3, 4 एवं उनकी माता विमला देवी के पक्ष में खातेदारी घोषित किये जाने के आदेश दिनांक 02.11.2018 को पारित किया जा चुका है, यदपि उस प्रकरण में मंदिर पक्षकार नहीं था किन्तु वादग्रस्त आराजी वही है जब पूर्व में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिवादी को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है तो उसी विषय वस्तु के



  
उपरवण्ड अधिकारी  
किशनगढ़ (अजमेर)

23  
लिए पुनः खातेदारी अधिकार की घोषणा करने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के उपरान्त अप्रार्थी सं० 6 लगायत 8 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी०पी०सी० वास्ते वाद पत्र खारिज किये जाने बाबत् सपठित धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद/प्रार्थना पत्र को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 14/05/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(A)  
(अर्चना चौधरी)

आर.ए.एस.  
उपखण्ड अधिकारी  
दिल्ली (अजमेर)